मेसर्स बेस्ट सेलर्स रिटेल (इंडिया) पी. वी. टी. लिमिटेड

बनाम

मेसर्स आदित्य बिरला नुवो लिमिटेड व अन्य

(2012 की सिविल अपील Nos.4313-14)

08 मई, 2012

[ए. के. पटनायक और स्वतंत्र कुमार, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 के साथ- अस्थाइ् निषेधाज्ञा रेंस्पोडेंन्ट संख्या 1 ने संपत्ति के संबंध में समझौते के विशिष्ठ निष्पादन के लिए आैर यदि समझौते के विशिष्ट निष्पादन को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो खर्चो आैर हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के विकल्प के लिए मुकदमा दायर किया - मुकदमें के साथ रेस्पोडेंट नंबर 1ने प्रतिवादियों को मुकदमें के निपटान तक किसी भी तरीके से संपत्ति को पटटे पर देने, उप-पटटे पर देने, हस्तान्तरित करने या उस पर कब्जा करने से रोकने के लिए अस्थाइ निषेधाज्ञा के लिए आवेदन दायर किया- निलची अदालत ने अस्थाइ निषेधाज्ञा के आवेदन की अनुमति दी- आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा- माना- सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 आैर 2 के तहत निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित करते समय इस पर विचार करना आवश्यक है। (1) क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है (2) क्या सुविधा का संतुलन

निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के पक्ष में है आैर (3) यदि प्रार्थना के अनुसार निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति होगी- तत्काल मामलें में निचली अदालत आैर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही थे कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला था- हालांकि, जहां प्रथम दृष्टमा मामला वादी के पक्ष में है, वहां भी अदालतों को अस्थाइ निषेधाज्ञा, वहां भी अदालतो को अस्थाई निषेधाज्ञा से इंकार कर देना चाहिए। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा के इंकार का कारण वादी को हुई चोट अपूरणीय नहीं है- वर्तमान मामलें में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने स्वयं क्षति की वैकल्पिक राहत का दावा किया था यदि प्रतिवादियों को मुकदमें की संपत्ति की अनुमति देने, पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने या उस पर कब्जा करने वाली अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की गई थी। और एक रेस्पाडेंट संख्या 1 अंततः मुकदमें में सफल हो गया, वह दावा किये गए और अदालत के समक्ष साबित किये गए नुकसान का हकदार होगा- रेस्पाडेंट संख्या 1 को अपूरणीय चोट नहीं होगी- अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश तदनुसार रद्द कर दिया जायेगा- विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963- धारा 37

वर्ष 2005 में, रेस्पोडेंट संख्या 1 ने लिबर्टी एजेंसियों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत लिबर्टी एजेंसियां संबंधित संपत्ति में रेस्पोडेंट संख्या 1 के उत्पादों को बेचने के लिए सहमत हुई और समझौते की अवधि की समाप्ति तक संपत्ति पर कब्जा बनाये रखने के लिए भी

सहमत हुई। और लिबर्टी एजेंसियों को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा आपूर्ति की गई के अलावा कोई अन्य वस्तु या सामान नहीं बेचना था। समझौते के तहत, लिबर्टी एजेंसियां प्रतिमाह एक निश्चित कमीशन की हकदार। इसके बाद रेस्पोडेंट संख्या 1 ने लिबर्टी एजेंसियों को समझौते के उल्लंघनों के बारे में सूचित किया, लेकिन लिबर्टी एजेंसियों ने उल्लंघनों को ठीक नहीं किया। परिणामस्वरूप, रेस्पोडेंट संख्या 1 को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कानूनी नोटिस जारी का आहान किया लिबर्टी एजेंसियों को समझौते की शर्तो का पालन करना होगा। हालांकि, लिबर्टी एजेंसियों ने दिनांकित 26.02.2010 एक पत्र भेजा ये दावा करते हुये कि साझेदारी फर्म का संविधान बदल गया है और उसके भागीदार ए. सी. तिरूमलराज सेवानिवृत हो गये है और संपत्ति के मालिक के रूप में ए. सी. तिरूमलराज ने संपत्ति की किरायेदारी लिबर्टी एजेंसियों के पक्ष में समाप्त कर दी।

रेस्पोडेंट संख्या 1 ने समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए और यदि समझौते को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो खर्चो और हानियों के लिए क्षतिपूर्ति के विकल्प के रूप में मुकदमा दायर किया। वाद के साथ रेस्पोडेंट संख्या 1 ने आदेश 39 नियम 1 और 2 सपठित धारा 151 के साथ एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें एक अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई, जिससे प्रतिवादियों को मुकदमें के निपटान तक किसी भी तरह से संपत्ति को पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने, अलग करने

या उस पर कब्जा करने से रोका जा सके। ट्रायल कोर्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की अनुमति दी और ए. सी. तिरूमलराज सहित लिबर्टी एजेंसियों और उसके सहयोगियों को किसी भी तरीक से संपत्ति को मुकदमें के निपटारे तक पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने, अलग करने या कब्जा करने से रोक दिया।

व्यथित, ए. सी. तिरूमलराज ने उच्च न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 तहत एक विविध अपील दायर की जबकि विविध अपील लंबित थी, इस एक आई ए में उच्च न्यायालय के ध्यान मंे लाया था रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में दिये गये अस्थाई निषेधाज्ञा के बावजूद, ए. सी. तिरूमलराज और बेस्ट सेलर्स रिटेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड वाद अनुसूचित संपत्ति में रहे थे जैक एंड जॉन्स के नाम से एक दुकान खोल रहे थे और एक अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने बेस्ट सेलर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड को रोक लगाई अनुसूचित संपत्ति में व्यवसाय करने से, उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक। बेस्ट सेलर्स रिटेल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने तक अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने विविध अपील को खारिज कर दिया और अंतरित आदेश को रद्द करने के आवेदन को खारिज कर दिया लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 को ट्रायल कोर्ट को यह वचन देने का निर्देश दिया कि यदि रेस्पोडेंट संख्या 1 मुकदमें में विफल रहता है, तो वह ए. सी. तिरूमलराज और बेस्ट सेलर्स

रिटेल प्राईवेट लिमिटेड को वाद अनुसूचित संपत्ति का उपयोग न करने के लिए नुकसान की भरपाई करेगा।

व्यथित, ए. सी. तिरूमलराज और बेस्ट सेलर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने यह तर्क देते हुए तत्काल अपील दायर की, कि निचली अदालतो को वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाने चाहिए थी।

अपीलों को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने मानाः कि 1.1 विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 37 यह स्पष्ट करती है कि अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा सीपीसी द्वारा विनियमित होनी चाहिए और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के प्रावधानों द्वारा नहीं।

वास्तव में, ट्रायल कोर्ट के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 के अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवेदन आदेश 39 नियम 1 और 2 सपठित धारा 151 के प्रावधानों के तहत यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित करते समय, न्यायालय को इस पर विचार करना आवश्यक है कि (1) क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला है, (11) क्या सुविधा का संतुलन निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के पक्ष में है और यदि प्रार्थना के अनुसार निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति होगी।

[पैरा 12] [846-सी-एफ]

1.2. तत्काल मामलें में, समझौते के खण्ड बी-2 को पढने पर, यह पाया गया कि लिबर्टी एजेंसियों ने वारंटी दी थी कि वाद अनुसूचित संपत्ति का स्वामित्व उसके पास था और वह समझौते की संपत्ति तक वाद अनुसूचित संपत्ति का कब्जा बरकरार रखेंगे। समझौते के खण्ड डी में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि समझौते की अवधि समझौते की तारीख से 12 साल की अवधि के लिए होगी जब तक की समझौते के प्रावधानों के अनुसार समाप्त ना हो जाये

खंड ई-2 अग्रे प्रदान करता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 और लिबर्टी एजेंसिया समझौते की तारीख से 6 साल की सपंत्ति के बाद कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर सकते है और रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इस खंड के तहत समझौता समाप्त नहीं किया। समझौते की तारीख से 6 साल की संपत्ति से पहले, लिबर्टी एजेंसियों ने रेस्पोडेंट संख्या 1 को दिनांक 26.02.2010 को पत्र भेजकर समझौते के खंड बी का उल्लंघन किया जिसमें यह प्रदान किया गया था कि लिबर्टी एजेंसियां समझौते की संपत्ति तक वाद अनुसूचित संपत्ति का कब्जा रखेगी। यह समझौते का उल्लंघन था जिसे ट्रायल कोर्ट ने अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा रोकने की मांग की थी इस प्रकार ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचने में सही थे।

कि रेस्पाडेंट संख्या 1 प्रथम दृष्ट्या मामला था

[पैरा 13] [846- जी-एच; 847-ए-डी]

किशोरसिंह रतनसिंह जडेजा बनाम मारुति निगम और ओआरएस।

(2009) 11 एससीसी 229: 2009 (5) एस. सी. आर. 527-निर्भर।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सेवा और अन्य।

(1991) 1 एससीसी 533: 1990 (3) पूरक। एससीआर 196; धारणा डी 'मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम। जहीर खान और अन्न। (2006) 4 एससीसी

227: 2006 (3) एस. सी. आर. 146-उद्धृत।

पेज वन रिकॉर्ड्स लिमिटेड बनाम ब्रिटन (1968) 1 डब्ल्यू. एल. आर. 157:

(1967) 3 सभी ई. आर. 822-उद्धृत।

2.1 फिर भी, कानून का स्थापित सिद्धांत यह है कि जहां प्रथम दृष्ट्या मामला वादी के पक्ष में है, तब भी न्यायालय अस्थाई निषेधाज्ञा से

इंकार कर देगी यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से इंकार करने के कारण वादी को हुई चोट अपूरणीय नहीं हो

[पैरा 14] [847-डी-ई]

2.2 वर्तमान मामले मंे प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं ही में नुकसान की वैकल्पिक राहत का दावा किया था यदि न्यायालय द्वारा विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत देने के लिए इंकार कर दिया गया तो रूपये 20,12,44,398 का भुगतान करना होगा। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दावा किये गये नुकसान के विवरण से पता चलता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने स्वयं समझौते की शेष सात वर्ष की अवधि के लिए 10,30,00,000 रूपये के रूप में लाभ की अनुमानित हानि की गणना की और स्टोर को दूसरी जगह स्थानान्तरित करने में 6,00,00,000 रूपये के नुकसान के अलावा 2,00,00,000 रूपये की सद्भावना हानि का आंकलन किया गया है।

847 -एच, 848 - ए; एफ-एच

2.3 वाद पत्र में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा किये गये नुकसान के प्रति इस दावे के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने यह माना है कि यदि मांगी गई अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी गई है, तो लिबर्टी एजेंसियां वाद अनुसूचित संपत्ति को पट्टे पर या उप-पट्टे पर दे सकती है या तीसरे पक्ष का हित बना सकती है और ऐसी स्थिति में कार्यवाही की बहुलता होगी।

और इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 को कठिनाई का सामना करना पडेंगा और उसकी मानसिक पीड़ा जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। रेस्पोडेंट संख्या 1 एक लिमिटेड कम्पनी है जो रेडिमेट कपड़ों का कारोबार करती है और कोई यह समझने में विफल है कि वित्तिय नुकसान के अलावा उसे कितनी मानसिक पीड़ा व कठिनाई होगी उच्च न्यायायल ने इसी तरह आक्षेपित निर्णय में कहा है कि यदि परीसर को किराये पर दिया जाता है , तो रेस्पोडेंट संख्या 1 को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और दावा की गई राहत विफल हो जायेगी और इसलिये, निषेधाज्ञा देना उचित है और ट्रायल कोर्ट ने सही फैसल किया है। लिबर्टी एजेंनसियों के भागीधारों को मुकद्में के निपटान तक सम्पत्ति को अलग करने, पट्टे पर देने, उप पट्टे पर देने या उस पर कब्जा करने से रोकने के लिये निषेधाज्ञा दी गई। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजर अंदाज कर दिया कि यदि लिबरटी एजेनसियों को उसके साझेदारों को मुकद्में की अनुसूची संपत्ति की अनुमति देने, पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने या उस पर कब्जा करने से रोकने वाली अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी, रेस्पोडेंट संख्या 1 अंततः मुकदमें में सफल हो गया, तो वह अदालत के समक्ष दावा किये गये और साबित किये गये नुकसान का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपूरणीय क्षति नहीं होगी।

दलपत कुमार और अन्र. वी. प्रह्लाद सिंह और अन्य। (1992) 1 एससीसी 719: 1991 (3) पूरक। एस. सी. आर. 472-पर निर्भर। अटॉर्नी-जनरल बनाम हैलेट 153 ई. आर. 1316: (1857) 16 एम. & W.569-संदर्भित।

3. निचली अदालत द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश फैसले को रदद किया जाता है। [पैरा 18] [849-जी-एच]

केस कानून संदर्भः

2009 (5) एससीआर 527	रिलायड आॅन	पैरा 6
1990 (3) एस. सी. आर.		साइर्टेड पैरा 8
2006 (3) एससीआर 146	साइर्टेड	साइर्टेड पैरा 8
(1967) 3 सभी ईआर 822		साइर्टेड पैरा 8
1991 (3) पूरक एस. सी. आर 472	रिलायड आॅन	पैरा 14
(1857) 16 एम. & W.569 रेफरड टू		पैरा 17

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या की 4313-14/ 2012

कनार्टक उच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 25.08.2010 से उत्पन्न।

के एम. एफ. ए. सं. 2010 की संख्या 4060 के साथ

2012 का सी. ए. सं. 4315।

अल्ताफ अहमद, ए. के. गांगुली, विक्रम गुरुनाथ, बालाजी श्रीनिवासन, जयक्रिती एस. जडेजा, जी. विक्रम, एस. श्रीनिवासन अपीलार्थी।

के. के. वेणुगोपाल, हरीश वी. शंकर, गोपाल शंकरनारायणन, राजेश डी. एम, ज्योति वी. के. अंसार अहमद उत्तरदाताओं के लिए चौधरी, मधुष्मिता बोरा।

एके पटनायक, जे, अनुमति दी गई.

2. ये 2010 के एमएफए नंबर 4060 और 2010 के एमसी नंबर 12036 और एमसी नंबर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश दिनांक 25.08.2010 के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के माध्यम से अपील हैं।

3. प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में यह हैं कि आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड प्रतिवादी नंबर 1 ने दोनों अपीलों में एक मुकदमा दायर किया, ओएस

नंबर 2010 की 1533 ।बेंगलुरु में जज. सिटी सिविल कोर्ट में लिबर्टी एजेंसियों, एक साझेदारी फर्म और उसके भागीदारों के खिलाफ 2010 का वादी में प्रतिवादी नंबर 1 का मामला इस प्रकार था: प्रतिवादी नंबर 1 विभिन्न प्रतिष्ठित ब्रांड नामों के तहत रेडीमेड कपड़ों और सहायक उपकरण के व्यवसाय में लगा हुआ था और वर्ष 1995 में उसने लिबर्टी एजेंसियों को इसके संचालन के लिए एक एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। प्रतिष्ठित ब्रांड नाम 'लुई फिलिप' के साथ रेडीमेड कपड़ों और सहायक उपकरणों का व्यवसाय। इसके बाद, 02.03.2005 को प्रतिवादी नंबर 1 ने लिबर्टी एजेंसियों के साथ एक नया समझौता किया, जिसके तहत लिबर्टी एजेंसियां सूट शेड्यूल संपत्ति में प्रतिवादी नंबर 1 के उत्पादों को बेचने के लिए सहमत हुईं और सूट शेड्यूल संपत्ति का कब्जा बनाए रखने के लिए भी सहमत हुईं। समझौते की अवधि समाप्त होने तक और लिबर्टी एजेंसियों को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा आपूर्ति की गई वस्तुओं के अलावा कोई अन्य लेख या सामान नहीं बेचना था। दिनांक 02.03.2005 (संक्षेप में 'समझौता') के समझौते के तहत, लिबर्टी एजेंसियां 7,50,000/- रुपये प्रति माह के एक निश्चित कमीशन की हकदार थीं और दिनांक 01.07.2008 के एक परिशिष्ट द्वारा लिबर्टी एजेंसियों को देय निश्चित कमीशन था। बढ़कर 9,62,500/- रूपये हो गया। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 1 ने लिबर्टी एजेंसियों को समझौते के नियमों और शर्तों के विभिन्न उल्लंघनों के बारे में सूचित किया, लेकिन लिबर्टी एजेंसियों ने उल्लंघनों को ठीक नहीं किया।

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी नंबर 1 को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। प्रतिवादी नंबर 1 ने 06.02.2010 को एक कानूनी नोटिस जारी किया जिसमें लिबर्टी एजेंसियों से समझौते की शर्तों का पालन करने का आह्वान किया गया। हालाँकि, लिबर्टी एजेंसियों ने 26.02.2010 को एक पत्र भेजकर दावा किया कि साझेदारी फर्म का संविधान बदल गया है और उसके भागीदार एसी थिरुमलराज सेवानिवृत्त हो गए हैं और सूट शेड्यूल संपत्ति के मालिक के रूप में एसी थिरुमलराज ने सूट शेड्यूल की किरायेदारी समाप्त कर दी है। लिबर्टी एजेंसियों के पक्ष में संपत्ति और प्रतिवादी नंबर 1 के दावे को हराने के इरादे से एक साजिशपूर्ण बेदखली की कार्यवाही शुरू की। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 1 ने समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए प्रार्थना की और यदि समझौते के विशिष्ट निष्पादन को न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो 20,12,44,398/- रुपये की राशि के खर्चों और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की।

4. मुकदमे के साथ, प्रतिवादी नंबर 1 ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 151 के साथ पढ़े गए आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन भी दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों को पट्टे देने से रोकने के लिए एक अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई। , मुकदमे का निपटारा होने तक किसी भी तरीके से वाद अनुसूची संपत्ति को उप-पट्टे पर देना, अलग करना या भारग्रस्त करना। लिबर्टी एजेंसियों और एसी थिरुमलराज ने अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर अपनी

आपत्तियां दर्ज कीं और अन्य बातों के साथ-साथ अपनी आपत्तियों में कहा कि सूट शेड्यूल संपत्ति का कब्जा बेस्ट सेलर्स रिटेल (आई) प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया है। लिमिटेड अतिरिक्त सिटी सिविल जज ने पक्षों को सुना और दिनांक 24.04.2010 के आदेश द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन की अनुमति दी और लिबर्टी एजेंसियों और एसी थिरुमलराज सहित उसके भागीदारों को किसी भी तरीके से सूट शेड्यूल संपत्ति को पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने, अलग करने या कब्जा करने से रोक दिया। मुकदमे का निपटारा लंबित है।

5. व्यथित, एसी थिरुमलराज ने उच्च न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 के तहत एक विविध अपील दायर की। जबकि विविध अपील लंबित थी, 2010 के आईए नंबर 1 में उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया कि प्रतिवादी नंबर 1, एसी थिरुमलाराज और बेस्ट सेलर्स रिटेल (आई) के पक्ष में दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा के बावजूद प्रा. लिमिटेड, सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी में 'जैक एंड जोन्स' के नाम से एक दुकान खोल रहे थे और 16.07.2010 के एक आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने बेस्ट सेलर्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड पर रोक लगा दी। लिमिटेड को उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक वाद अनुसूची संपत्ति में व्यवसाय करने से रोक दिया गया है। बेस्ट सेलर्स रिटेल (आई) प्रा. लिमिटेड ने तब अंतरिम आदेश दिनांक 16.07.2010 को रद्द करने के लिए 2010 का एक आवेदन एमसी नंबर 12036 दायर किया।

हालाँकि, आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने विविध अपील को खारिज कर दिया और अंतरिम आदेश को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया, लेकिन प्रतिवादी नंबर 1 को ट्रायल कोर्ट को एक वचन देने का निर्देश दिया कि यदि प्रतिवादी नंबर 1 मुकदमे में विफल रहता है, यह एसी थिरुमलाराज और बेस्ट सेलर्स रिटेल (आई) प्राइवेट लिमिटेड को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। सूट अनुसूची संपत्ति का उपयोग नहीं करने के लिए लिमिटेड। एग्रीवेड, एसी थिरुमलाराज और बेस्ट सेलर्स (आई) प्रा. लिमिटेड ने ये सिविल अपीलें दायर की हैं।

6. श्री अल्ताफ अहमद और श्री एके गांगुली, दोनों अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने किशोरसिंह रतनसिंह जाडेजा बनाम मारुति कॉर्पोरेशन और अन्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया । [(2009) 11 एससीसी 229] आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करते समय, न्यायालय को इस पर विचार करना है (i) क्या वादी के पास प्रथम दृष्टया मामला है; (ii) क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है; और (iii) यदि निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति और चोट होगी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने स्वयं अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा तय नहीं होने की स्थिति में वैकल्पिक राहत के रूप में 20,12,44,398/- रुपये के नुकसान का दावा किया है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि वादी ने स्वयं प्रतिवादियों द्वारा

समझौते के कथित उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया था, इसलिए अदालत को वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं देनी चाहिए थी।

7. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14(1) खंड (बी) में प्रावधान है कि एक अनुबंध जो इतने सूक्ष्म या असंख्य विवरणों में चलता है या जो व्यक्तिगत योग्यता या इच्छा पर निर्भर है। पार्टियों का, या अन्यथा इसकी प्रकृति ऐसी है कि अदालत अपनी भौतिक शर्तों के विशिष्ट निष्पादन को लागू नहीं कर सकती है, ऐसे अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसी तरह खंड (डी) में धारा 14(1) में प्रावधान है कि एक अनुबंध, प्रदर्शन जिसमें एक निरंतर कर्तव्य का प्रदर्शन शामिल है जिसकी अदालत निगरानी नहीं कर सकती है, एक अनुबंध है जिसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि लिबर्टी एजेंसियों और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच समझौता एजेंसी का एक अनुबंध है और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 (1) के खंड (बी) और (डी) के तहत कवर किया गया है और ऐसा है जिसे विशेष रूप से नहीं किया जा सकता है। लागू किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14(1) के खंड (सी) में आगे प्रावधान है कि एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति में निर्धारित करने योग्य है, उसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि समझौते की तारीख से छह साल पूरे होने पर, लिबर्टी एजेंसियां समझौते को समाप्त कर

सकती हैं और छह साल की अवधि वर्ष 2011 में समाप्त हो गई थी और इसलिए अदालत अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं कर सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 41 विशिष्ट राहत अधिनियम , 1963 के (ई) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी अनुबंध के उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती, जिसके निष्पादन को लागू नहीं किया जाएगा।

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस एंड अन्य में निर्णय का हवाला दिया । [(1991) 1 एससीसी 533] जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि एक अनुबंध जो अपनी प्रकृति में निर्धारित करने योग्य है, उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उन्होंने परसेप्ट डी'मार्क (इंडिया) (पी) लिमिटेड बनाम जहीर खान और अन्य मामले के फैसले का भी हवाला दिया । [(2006) 4 एससीसी 227] जिसमें इस न्यायालय ने पेज वन रिकॉर्ड्स लिमिटेड बनाम ब्रिटन [(1968) 1 डब्लूएलआर 157: (1967) 3 ऑल ईआर 822] में चांसरी डिवीजन के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा है कि कहां पार्टियों के बीच दायित्वों की समग्रता एक प्रत्ययी संबंध को जन्म देती है, निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी क्योंकि प्रत्ययी संबंध में पार्टी पर लगाए गए कर्तव्यों का प्रदर्शन दूसरे पक्ष के कहने पर लागू नहीं किया जा सकता है।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि लिबर्टी एजेंसियों और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच समझौता एक एजेंसी समझौता था और इसने सूट अनुसूची संपत्ति में किसी भी तरह का कोई हित पैदा नहीं किया और इसलिए, प्रतिवादी नंबर 1 इसका हकदार नहीं था। मुकदमे की अनुसूची संपत्ति के मालिक को किसी तीसरे पक्ष के साथ किसी भी तरीके से संपत्ति का सौदा करने से रोकने वाले किसी भी निषेधाज्ञा के लिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी मामले में चूंकि प्रतिवादियों ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पर अपनी आपत्तियों में स्पष्ट रूप से कहा था कि सूट अनुसूची संपत्ति का कब्जा पहले ही तीसरे पक्ष, बेस्ट सेलर्स रिटेल (आई) प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया था। लिमिटेड, ट्रायल कोर्ट को तीसरे पक्ष को प्रतिवादी के रूप में शामिल किए बिना कोई निषेधाज्ञा नहीं देनी चाहिए थी। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा तीसरे पक्ष के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

10. श्री केके वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि समझौते के खंड बी-2 के तहत, लिबर्टी एजेंसियों ने वारंटी दी थी कि सूट शेड्यूल संपत्ति का स्वामित्व उसके पास है और वह दूसरी ओर, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील यह समझौते की समाप्ति तक सूट अनुसूची संपत्ति पर कब्ज़ा बनाए रखेगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि समझौते के खंड

डी के तहत समझौते की अवधि समझौते की तारीख से बारह साल की अवधि के लिए थी और यह अवधि 2017 में समाप्त होनी थी और इसलिए, यह सही नहीं है, जैसा कि तर्क दिया गया है अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि अनुबंध की अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि समझौते के खंड ई-2 के तहत केवल प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी को समझौते की तारीख से छह साल की समाप्ति के बाद कम से कम तीन महीने की लिखित सूचना देकर समझौते को समाप्त करने का अधिकार था और इसलिए लिबर्टी एजेंसियों को समझौते को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए, लिबर्टी एजेंसियों की ओर से कोई विवाद नहीं उठाया जा सकता है कि अनुबंध प्रकृति में निर्धारित था या अनुबंध समाप्त हो गया था।

11. इस तर्क के उत्तर में कि विशिष्ट राहत अधिनियम , 1963 की धारा 14(1)(बी) और (डी) के तहत समझौते को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, श्री वेणुगोपाल ने प्रस्ताव के लिए एजेंसी पर बोस्टेड और रेनॉल्ड्स का हवाला दिया कि असाधारण रूप से किसी एजेंसी के अनुबंध के विशिष्ट निष्पादन के मामले में न्यायालय द्वारा भी आदेश दिया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 42 यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करती है कि जहां एक अनुबंध में एक निश्चित कार्य करने के लिए एक सकारात्मक समझौता शामिल होता है, एक नकारात्मक समझौते के साथ मिलकर, एक निश्चित कार्य न करने के

लिए अभिव्यक्त या निहितार्थ, ऐसी परिस्थितियाँ जो अदालत सकारात्मक समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए बाध्य करने में असमर्थ है और उसे नकारात्मक समझौते के निष्पादन के लिए निषेधाज्ञा देने से नहीं रोकेगी। उन्होंने 22 Ch.D में रिपोर्ट किए गए डोनेल बनाम बेनेट में चांसरी डिवीजन के फैसले का भी हवाला दिया। 835 जहां यह माना गया है कि जहां समझौते में कोई नकारात्मक खंड है, अदालत को इस सवाल पर ध्यान दिए बिना इसे लागू करना होगा कि क्या पूरे अनुबंध का विशिष्ट प्रदर्शन दिया जा सकता है। उन्होंने समझौते के खंड बी-5 का उल्लेख किया जो यह प्रावधान करता है कि लिबर्टी एजेंसियां केवल प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों को बेचेंगी और परिसर में किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/फर्म द्वारा निर्मित कोई अन्य लेख/उत्पाद नहीं बेचेंगी। समझौते की अवधि जब तक कि प्रतिवादी नंबर 1 कंपनी द्वारा अनुमोदित न हो। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय से किसी भी राहत के हकदार हैं।

12. विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 14 , 41 और 42 के प्रावधानों के आधार पर पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों से निपटना हमारे लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 37 यह स्पष्ट करती है कि अस्थायी निषेधाज्ञा सीपीसी द्वारा विनियमित किया जाना है न कि विशिष्ट राहत अधिनियम , 1963 के प्रावधानों द्वारा। वास्तव में, ट्रायल

कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी नंबर 1 के अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन आदेश 39 नियम 1 और 2 के प्रावधानों के तहत है। सीपीसी की धारा 151. यह इस न्यायालय द्वारा किशोरसिंह रतनसिंह जाडेजा बनाम मारुति कॉर्पोरेशन और अन्य में आयोजित किया गया है । (सुप्रा) कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित करते समय, न्यायालय को इस पर विचार करना आवश्यक है (i) क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है; (ii) क्या सुविधा का संतुलन निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के पक्ष में है; और (iii) यदि प्रार्थना के अनुसार निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं किया गया तो क्या वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए, हमें केवल इस बात पर विचार करना होगा कि क्या अस्थायी निषेधाज्ञा देने से संबंधित इन सुस्थापित सिद्धांतों को ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा गया है।

13. समझौते के खंड बी-2 को पढ़ने पर, हम पाते हैं कि लिबर्टी एजेंसियों ने एक वारंटी दी थी कि सूट अनुसूची संपत्ति का स्वामित्व उसके पास था और वह समझौते की समाप्ति तक सूट अनुसूची संपत्ति पर कब्जा बनाए रखेगी। . समझौते के खंड डी में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि समझौते की अवधि समझौते की तारीख से बारह वर्ष की अवधि के लिए होगी जब तक कि समझौते के प्रावधानों के अनुसार समाप्त न हो जाए। खंड ई-2 में यह प्रावधान है कि प्रतिवादी संख्या 1 और लिबर्टी

एजेंसियां समझौते की तारीख से छह साल की समाप्ति के बाद कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर सकती हैं और प्रतिवादी संख्या 1 ने इसे समाप्त नहीं किया है। इस खंड के तहत समझौता. समझौते की तारीख से छह साल की समाप्ति से पहले, लिबर्टी एजेंसियों ने प्रतिवादी नंबर 1 को दिनांक 26.02.2010 को पत्र भेजकर समझौते के खंड बी-2 का उल्लंघन किया, जिसमें प्रावधान था कि लिबर्टी एजेंसियां मुकदमे का कब्जा बरकरार रखेंगी। अनुबंध की समाप्ति तक संपत्ति का शेड्यूल करें। यह समझौते का उल्लंघन था जिसे ट्रायल कोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा रोकने की मांग की थी। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही थे कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास प्रथम दृष्टया मामला था।

14. फिर भी, कानून का स्थापित सिद्धांत यह है कि जहां प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है, वहां भी अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार कर देगी यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार करने के कारण वादी को हुई चोट अपूरणीय नहीं है। दलपत कुमार और अन्य में। प्रह्लाद सिंह और अन्य । [(1992) 1 एससीसी 719] इस न्यायालय ने कहा: "यह संतुष्टि कि प्रथम दृष्टया मामला अपने आप में निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को यह भी संतुष्ट करना होगा कि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करने से राहत चाहने वाले पक्ष को "अपूरणीय क्षति" होगी और निषेधाज्ञा देने के अलावा पक्ष के पास कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है

और उसे पकड़े गए परिणामों से सुरक्षा की आवश्यकता है। चोट या बेदखली. हालाँकि, अपूरणीय चोट का मतलब यह नहीं है कि चोट की मरम्मत की कोई भौतिक संभावना नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब केवल यह है कि चोट भौतिक होनी चाहिए, अर्थात्, क्षति के माध्यम से पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

15. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं वादपत्र में 20,12,44,398/- रुपये की क्षति की वैकल्पिक राहत का दावा किया था यदि विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी और वादपत्र में दावा किए गए 20,12,44,398/- रुपये के नुकसान का विवरण इस प्रकार है:

"मैं। 28.02.2010 को नेट बुक स्टॉक राशि 1,15,97,638/- रुपये है।

द्वितीय. 27.01.2010 को देय ऋण राशि रु. 44,81,584/- है।

तृतीय. 28.02.2010 को लेखा विवरण के अनुसार देय राशि रु. 20,65,176/- है।

चतुर्थ. एजेंसी अनुबंध की शेष 7 वर्ष की अवधि के लिए बिक्री पर लाभ की अनुमानित हानि रु.10,31,00,000/- है।

V. विज्ञापन पर खर्च की गई राशि सहित सद्भावना, प्रतिष्ठा की हानि रु. 2,00,00,000/-।

VI. स्टोर को ब्रिगेड रोड, बैंगलोर में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने और शेष अवधि 7 वर्षों तक अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए वादी को होने वाली राशि की हानि साधारण ब्याज के साथ 6,00,00,000/- रुपये होगी। भुगतान की तारीख से लेकर वसूली तक 24% प्रति वर्ष की दर, क्योंकि यह एक वाणिज्यिक लेनदेन है।"

16. हालांकि, प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री वेणुगोपाल ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 के भविष्य के लाभ और सद्भावना की हानि की गणना धन के संदर्भ में नहीं की जा सकती है, लेकिन नुकसान का उपरोक्त विवरण दावा किया गया है। वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 यह दर्शाएगा कि प्रतिवादी संख्या 1 ने समझौते की शेष सात वर्ष की अवधि के लिए लाभ की अनुमानित हानि की गणना 10,31,00,000/- रुपये के रूप में की है और सद्भावना की हानि का भी आकलन किया है। ब्रिगेड रोड, बैंगलोर में स्टोर को दूसरी जगह स्थानांतरित करने में 6,00,00,000/- रुपये के नुकसान के अलावा 2,00,00,000/- रुपये।

17. वादपत्र में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किए गए नुकसान के प्रति इस दावे के बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने माना है कि यदि मांगी गई अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गई है, तो लिबर्टी एजेंसियां सूट अनुसूची संपत्ति को पट्टे पर या उप-पट्टे पर दे सकती हैं या तीसरा निर्माण कर सकती हैं। पार्टी का हित उससे ऊपर है और ऐसी स्थिति में, कार्यवाही की बहुलता होगी और इस प्रकार प्रतिवादी नंबर 1 को कठिनाई और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, जिसकी भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती है। प्रतिवादी नंबर 1 एक लिमिटेड कंपनी है जो रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय करती है और हम यह समझने में विफल हैं कि वित्तीय नुकसान के अलावा इसे कितनी मानसिक पीड़ा और कठिनाई होगी। उच्च न्यायालय ने इसी तरह आक्षेपित निर्णय में कहा है कि यदि परिसर को किराए पर दिया जाता है, तो प्रतिवादी नंबर 1 को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और दावा की गई राहत विफल हो जाएगी और इसलिए, निषेधाज्ञा देना उचित है और ट्रायल कोर्ट ने कहा है मुकदमे के निपटान तक लिबर्टी एजेंसियों के साझेदारों को संपत्ति को अलग करने, पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने या उस पर कब्ज़ा करने से रोकने के लिए उचित रूप से दी गई निषेधाज्ञा दी गई है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि यदि लिबर्टी एजेंसियों और उसके साझेदारों को मुकदमे की अनुसूची संपत्ति की अनुमति देने, पट्टे पर देने, उप-पट्टे पर देने या उस पर कब्ज़ा करने से रोकने वाली अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी, और प्रतिवादी नंबर 1

अंततः मुकदमे में सफल हुआ, तो यह दावा किया गया और अदालत के समक्ष साबित किया गया हर्जाना पाने का हकदार होगा। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादी नंबर 1 को अपूरणीय क्षति नहीं होगी। द अटॉर्नी-जनरल बनाम हैलेट [153 ईआर 1316: (1857) 16 एम. एंड डब्लू.569] में एल्डरसन, बी. के शब्दों को उद्धृत करने के लिए:

> "मैं अपूरणीय क्षति का अर्थ यह मानता हूं कि यदि निषेधाज्ञा द्वारा रोका नहीं गया है, तो बाद में किसी भी डिक्री द्वारा क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है जिसे न्यायालय कारण के परिणाम में सुना सकता है।"

18. उपरोक्त कारणों से, हम ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के साथ-साथ आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय के दिनांक 16.07.2010 के आदेश को रद्द करते हैं। लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ओम प्रकाश नायक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।